Result Mitra Daily Magazine

मोदी 3.0 में भारतीय विदेश नीति : विद्यमान चुनौतियां और आगामी अवसर

चर्चा में क्यों?

नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के महज एक हफ्ते में वह G-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा पर हैं।

इससे विशेषज्ञों द्वारा यह कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि मोदी 3.0 में विदेश नीति कैसी हो सकती है?

भारत और पड़ोसी देश

- भारत के सात पड़ोसी देशों - बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स - के नेता नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार को आमंत्रित नहीं किया गया।
- किसी भी पड़ोसी नेता के साथ कोई ठोस द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई।

पाकिस्तान

- 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था।
- लेकिन 2016 में पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों के बाद दोनों देशों के मध्य संबंध खराब हो गए।
- 2019 में पुलवामा हमले और बालाकोट हमलों ने भारत में राष्ट्रवादी भावना को आहत किया।

- अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों में गिरावट आई।
- 2019 में प्रधानमंत्री रहे इमरान खान जेल में हैं, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है
- और शरीफ परिवार, जिन्हें अब सेना का समर्थन प्राप्त है, फिर से सत्ता में आ गए हैं।
- हालांकि "सुरक्षा" - यानी पाक समर्थित आतंकवाद का मुकाबला करना - भारत की प्राथमिकता है।
- पिछले एक दशक से देश की नीति यही रही है कि "आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।"
- पिछले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों ने संभावित बातचीत की संभावना को खत्म कर दिया।

अफ़ग़ानिस्तान

- अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत के काबुल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है।
- मानवीय सहायता में मदद करने के लिए नियुक्त एक तकनीकी टीम के माध्यम से निम्न-स्तरीय जुड़ाव है,
- लेकिन अभी उच्च-स्तरीय जुड़ाव से इनकार किया गया है।
- हालांकि दोनों के मध्य कामकाजी संबंध जारी रहने की संभावना है।

म्यांमार

- अक्टूबर 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद से म्यांमार की सरकारी सेना रक्षात्मक मुद्रा में है।
- भारतीय राजनीतिज्ञों ने यह सुझाव दिया गया है कि सरकार के गिरने की संभावना को देखते हुए, भारत को विपक्षी समूहों से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए।

मालदीव

- हालिया शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की यात्रा, जो "इंडिया आउट" के नारे के साथ सत्ता में आए थे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी।
- मुइज़्ज़ू सरकार के अनुरोध पर भारत द्वारा मालदीव में भारतीय वायु सेना के सैन्य कर्मियों को हटाकर प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करने के बाद, नई दिल्ली और माले बातचीत के लिए तैयार दिखाई दिए।

बांग्लादेश

- यद्यपि "घुसपैठियों" के बारे में चुनावी बयानबाजी ने अक्सर ढाका के साथ संबंधों को खराब किया है।
- मोदी 3.0 के दौरान सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा अधिक संयम बरतना फायदेमंद साबित हो सकता है,
- क्योंकि दोनों देशों का साझा उद्देश्य उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद का मुकाबला करना है।

भूटान

- भारत , भूटान को उसकी पंचवर्षीय योजना, वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना में सहायता देने के लिए तैयार है।

Result Mitra

- खासकर तब जब चीन अपनी शर्तों पर भूटान के साथ सीमा पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है।
- भारत चाहता है कि भूटान, जो दो एशियाई दिग्गजों के बीच फंसा हुआ है, उसके पक्ष में हो।

नेपाल

- नेपाल के साथ संबंध एक नाजुक चुनौती पेश करते हैं।
- नेपाल में चीन की मजबूत राजनीतिक पकड़ है, और काठमांडू की सरकार जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक महत्वपूर्ण कारक हैं,
- माना जाता है कि वह भारत के खिलाफ चीनी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।
- नेपाल की एकतरफा रूप से फिर से बनाई गई सीमाओं को राष्ट्रीय मुद्रा पर रखने का निर्णय बताता है, कि दोनों देशों के मध्य नाजुकता बनी रहेगी।
- वहीं भारत को नेपाली लोगों का विश्वास फिर से हासिल करना होगा, जिसे 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के बाद झटका लगा था।

श्रीलंका

- श्रीलंका के आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के बाद भारत ने श्रीलंका के द्वारा जो सद्भावना अर्जित की थी,
- वह तमिलनाडु में चुनावों से पहले कच्चातीवु मुद्दे को बेवजह उछालने से दोनों देशों के मध्य थोड़ी दूरियाँ आ गई।
- हालांकि इस साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले वित्तीय सहायता के साथ-साथ निवेश के ज़रिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना भारत के लिए एक अहम काम होगा।

सेशेल्स और मॉरीशस

- इन देशों में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में मदद करने की भारत की योजना समुद्री कूटनीति और सुरक्षा प्रयास का हिस्सा है।
- मॉरीशस में अगालेगा द्वीप पर कुछ सफलता मिली है, लेकिन सेशेल्स में असम्पशन द्वीप को विकसित करना एक चुनौती बन गया है।

भारत और पश्चिमी देश

- मोदी सरकार पश्चिमी देशों के साथ अधिक सक्रिय रही है जिसे पिछली कई सरकारों की तुलना में ज़्यादा लेन-देन करने वाली मानी जा सकती है।
- इसने अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध भी विकसित किए हैं।
- आदर्श परिदृश्य यह होगा कि भारतीय हितों की रक्षा की जाए और पश्चिमी पूंजी और प्रौद्योगिकी से लाभ उठाया जाए, जबकि उसे अपने घरेलू मामलों पर व्याख्यान नहीं दिया जाए।
- अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को दोनों दलों का समर्थन प्राप्त है
- नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से इस पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।
- रक्षा और अत्याधुनिक तकनीक ही आगे चलकर दोनों देशों के मध्य संबंधों को आगे बढ़ाएगी।
- फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में सुधार हुआ है,

Result Mitra

- और ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के लिए उत्सुक है।
- भारत और यूरोपीय संघ भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पारस्परिक लाभ के लिए FTA करने के इच्छुक हैं।
- खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा रही है।
- कनाडा के साथ राजनीतिक संबंध तब से गिरावट की स्थिति में हैं, जब से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक और खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया है,
- अपितु 2025 के कनाडाई चुनावों तक संबंध तनावपूर्ण बने रहने की संभावना है।
- हालांकि, आर्थिक संबंधों और कनाडा में छात्रों के प्रवाह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है।

चीन की चुनौती

- दोनों देशों के बीच सीमा गतिरोध अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश करने वाला है, और मोदी 3.0 के समक्ष कार्य कठिन और पेचीदा है।
- भारत के अनुसार जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता।
- भारत पूरी तरह से सैनिकों को पीछे हटाना और फिर तनाव कम करना चाहता है, और सीमा के दोनों ओर से 50,000-60,000 सैनिकों और हथियारों को हटाने में बहुत समय लगेगा।
- जुलाई के प्रथम सप्ताह में कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक, इस दिशा में कदम बढ़ाने की संभावना पैदा कर सकती है।

रूसी समस्या

- यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस के साथ भारत के संबंधों की परीक्षा हो रही है।
- रक्षा आवश्यकताएं भारत की रूस पर निर्भरता का मुख्य कारण हैं,
- सस्ते तेल की उपलब्धता ने अब ऊर्जा को भी इसमें शामिल कर दिया है।
- रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के सामने नहीं झुका है, तथा अब व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि युद्ध में उसका पलड़ा भारी है।
- भारत द्वारा स्विटजरलैंड में 15-16 जून को होने वाले शांति सम्मेलन में भाग न लेने की संभावना है, क्योंकि रूस इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा।
- लेकिन भारत से आधिकारिक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने और संवाद तथा कूटनीति पर जोर देने की उम्मीद है।
- मोदी 3.0 के तहत भारत की कोशिश होगी कि शांति के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को बातचीत हेतु साथ लाया जाए,
- हालांकि भारत इस सब में खुद को हानि नहीं पहुंचाना चाहेगा।

पश्चिम एशिया में भावी संभावना

- मोदी 1.0 और 2.0 ने सऊदी अरब से लेकर इजरायल, यूएई से लेकर ईरान, कतर से लेकर मिस्र तक के क्षेत्र के देशों और नेताओं के साथ संबंध बनाए हैं।
- ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और क्षेत्र में 9 मिलियन की संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासी भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे हैं।

Result Mitra

- भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, आई2यू2 समूह (India, Israel, United Arab Emirates, & United States), और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण पारगमन गलियारा (INSTC) सभी को गेम चेंजर माना जाता है,
- हालांकि इजरायल-हमास संघर्ष ने भारत सहित विश्व के समक्ष अनिश्चितता उत्पन्न की है।

Result Mitra